ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 5, September 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 औ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का तुलनात्मक अध्ययन

Surendra Singh

Assistant Professor, Sociology, S.B.R.M. Government College, Nagaur, Rajasthan, India

सार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पर अधिक बल दिया गया है जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं को दूर करने पर अधिक बल दिया गया है।

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 rashtriy Shiksha niti 1986 को ही प्रभावी शिक्षा नीति के रूप में स्वीकार किया गया है।

इस में सर्वप्रथम सुधार शिक्षा के ढांचे में किया गया शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए 10+2+3 व्यवस्था को अपनाया गया। जिसमें देश की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। इसमें ऐसी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई जिससे लोकतंत्र पर उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक लोकतंत्र शिक्षा के गुणों को प्रमुख स्थान दिया गया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित कर दिया गया।
सभी शिक्षा के स्तर हेतु पाठ्यक्रम के योजना के निर्माण की तैयारी भी की गई।[1,2]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़ा गया। समाज की वास्तविक आवश्यकताओं का अध्ययन कर छात्रों को समाज के लिए तैयार करने हेतु छात्रों के व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं को प्रमुख स्थान दिया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया। जिससे वह भावी जीवन के लिए जीविकोपार्जन हेतु तैयार हो सके।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु जिनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया गया-

•राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया।

•राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा देश के लगभग 90% लोगों को प्राप्त है तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गणित व विज्ञान विषय को अनिवार्य कर दिया गया।

•इस शिक्षा नीति को 12 भागों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक भाग का संबंध किसी ना किसी विषय क्षेत्र से है
•शिक्षा के उत्तम क्रियान्वयन हेतु शिक्षा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को केंद्र सरकार ,राज्य सरकार एवं जिले के अनुसार विभाजित किया गया।[3,5]

•इसमें छात्रों के व्यावहारिक पक्ष एवं शारीरिक पक्ष पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा में इनको मुख्य स्थान दिया गया जिससे शिक्षा के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके।

•राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया एवं बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा के स्वरूप को स्वीकार किया गया।

•मई 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मूलभूत सामग्री उपलब्ध कराना था। प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए ब्लैक बोर्ड योजना का निर्माण किया गया एवं 90% छात्रों को किसके द्वारा लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी का निर्माण किया गया।
•इस शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए गति निर्धारित विद्यालयों की स्थापना की गई जैसे - नवोदय विद्यालय इसके अलावा वर्तमान समय में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ,आश्रम पद्धति विद्यालय ,विद्याज्ञान स्कूल यह सभी गति निर्धारक विद्यालयों की श्रेणी में आते हैं।

•सन 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) District Primary Education Program की शुरुआत की गई। व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में 1921 में कानपुर में (HBTI) Harcourt Buttler Technical Institute की स्थापना की गई।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दोष
•इस शिक्षा नीति में केंद्र एवं राज्य सरकारों के शैक्षिक अधिकार एवं उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किए गए हैं।

•वित्त के क्षेत्र में जन सहयोग के स्थान पर जन शोषण हो रहा है।[7]

•प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या का अनुपालन आज तक नहीं किया जा सका है।

विचार-विमर्श

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के सामान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा ,उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाने के लिए बनाई गई थी। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के दोषों को दूर करना तथा भारतीय शिक्षा संरचना को और अधिक दुरुस्त करना था। पूर्व- इसरो प्रमुख और पदम विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया इस समिति में अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य हैं शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाने के लिए बनाई गई थी । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कृषि शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किताबों के उत्पादन व्यवस्थित आंकड़े उनकी लागत तथा सुलभता पर ध्यान देना सुनिश्चित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में परीक्षा में विश्वसनीयता वैधता तथा मूल्यांकन को सूचित पूर्ण ढंग से लागू करने पर बल दिया।

परिणाम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ऐसी नीति थी जिसको सफलतापूर्वक लागू करने का संपूर्ण प्रयास किया गया परंतु यह कहना गलत होगा कि यह अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रही यह हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली सभी को रोजगार प्राप्त करवाने हेतु असमर्थ साबित हुई है।[**4**,**6**]

पढ़ों, लिखा है दीवारों पर मेहनतकश का नारा

पढ़ों, पोस्टर क्या कहता है, वो भी दोस्त तुम्हारा

पढ़ों, अगर अंध विश्वासों से पाना है छुटकारा

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

पढ़ों, किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा

सफदर हाशमी का यह मशहूर गीत न केवल जीवन में शिक्षा की आवश्यकता बल्कि उसके महत्त्व को भी रेखांकित करता है। जीवन में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तैयार करने के लिये विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव माँगे गए थे।

प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।[2,3]

भारतीय शिक्षा की विकास विकास यात्रा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968
  - स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पर आधारित थी।
  - शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित किया गया।
  - 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस।
  - नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था।
  - शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा।
  - माध्यमिक स्तर पर 'त्रिभाषा सूत्र' लागू करने का आह्वान किया गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
  - इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष ज़ोर देना था।
  - इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" लॉन्च किया।
  - इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया।
  - ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित "ग्रामीण विश्वविद्यालय" मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन, 1992
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था।
  - इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination-JEE) और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (All India Engineering Entrance Examination-AIEEE) तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिये राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (SLEEE) निर्धारित की।[5,7]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 5, September 2023 |

- इसने प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया।

निष्कर्ष

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development- MHRD) का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' (Education Ministry) करने को भी मंज़ूरी दी गई है।[7]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1) राष्ट्रीय शिक्षा
2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 प्रारूप (प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुट)
4) शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की तैयारी, बदलेगी शिक्षा नीति (मई-जून २०१९)
5) "नई शिक्षा नीति", विकिपीडिया, 2020-12-22, अभिगमन तिथि 2021-01-04
6) ↑ "नई शिक्षा नीति 2020", विकिपीडिया, 2020-12-23, अभिगमन तिथि 2021-01-04
7) ↑ नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति : महत्त्व व चुनौतियाँ

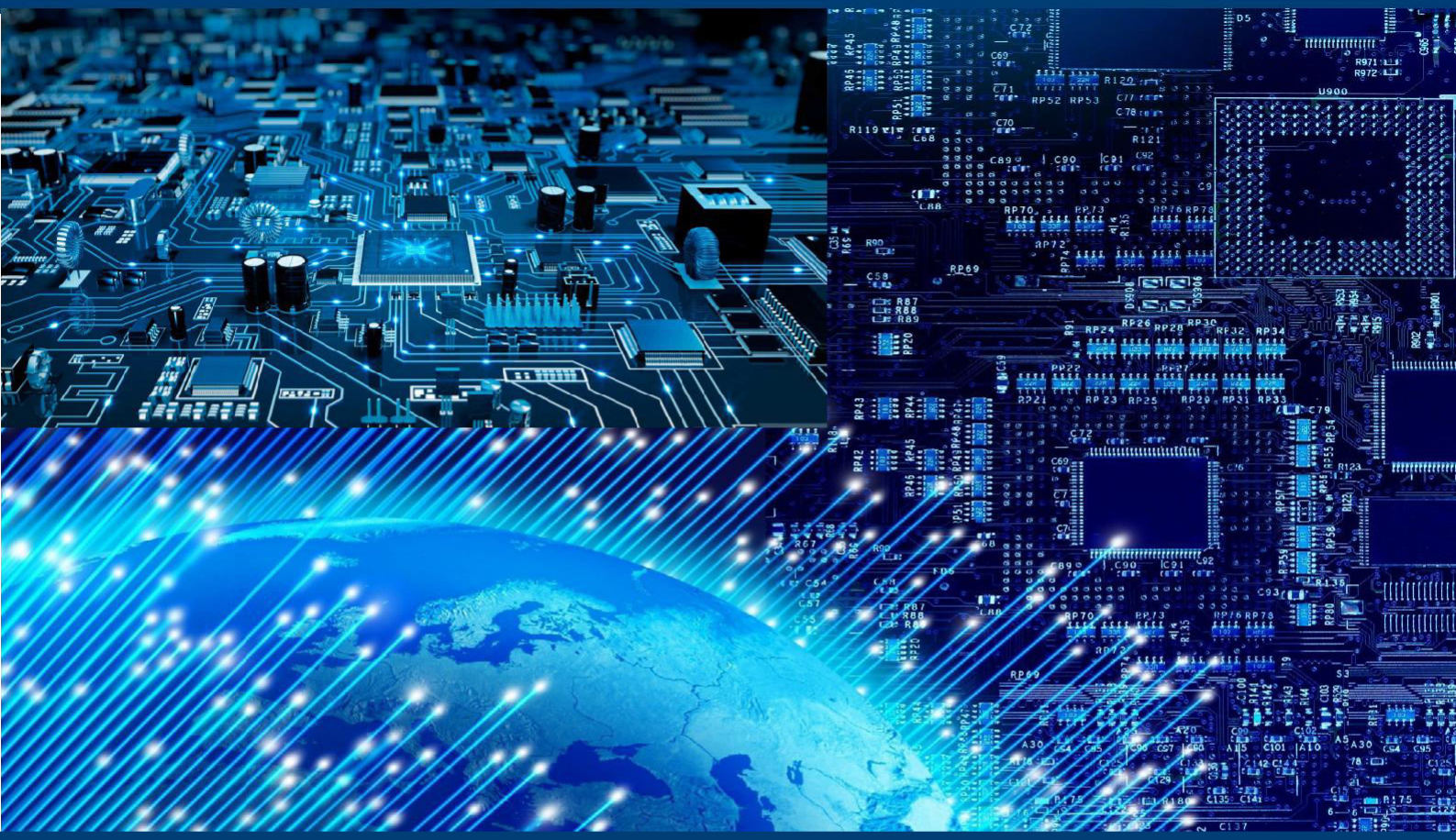

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |